

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

दोस्रो संख्या:-27 /2017

(223 आर.टी.एक्ट)

सी.एम.एस .संख्या:-2017 /00143

उनवान

क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर।

2 जिला वन अधिकारी व करौली जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर जिला करौली
राजस्थान।

.....अपीलांटस्।

बनाम

1. छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र थौलू जाति मीना निवासी रूधपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली।
2. तहसीलदार तहसील मासलपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:-

1. श्री श्याम बाबू शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 02।

--:निर्णय:-

दिनांक: 05.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली में दाखल बाद पत्र संख्या 175/2005 वउनवान छोटू उर्फ छोटेलाल बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के विरुद्ध अंतर्गत काला 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी छोटेलाल ने एक बाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादगण विवादित आराजीयात पर मदाखलत करने की धमकी देते है। जबकि विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। वादी ने प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन मातहत अदालत के समक्ष किया। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली ने दिनांक 15.12.2016 को निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर



व डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 5 लगायत 17 कुल रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम केसपुरा तहसील मासलपुर में स्थित है। जो वन विभाग के कब्जे की आराजीयात है। जो कि वन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी करौली की रिपोर्ट जिसको आरक्षित वन खाण्ड वासंवाडी रेणज करौली के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग से क्रमांक 19, 50 और 55 दिनांक 09.11.55 से राजपत्र दिनांक 17.12.55 से प्रकाशित हुई। जिसके तहत उक्त खसरा नम्बर को वन क्षेत्र के लिये राज्य सरकार ने वन विभाग के आरक्षित कर दिया गया। रेस्पोंड का उक्त आराजीयात के कोई संबंध नहीं रहा है ना ही उक्त आराजीयात को काश्त किया है। आराजीयात पर वन विभाग के दरख्त पेड़ खड़े हुये है जो वन विभाग के कब्जे में है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है। अतः मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 15.12.2016 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजीयात को वन विभाग ने आरक्षित करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से शासन सचिव द्वारा प्रपत्र विज्ञप्ति एफ 7,20,21,63 दिनांक 14.02.63 द्वारा उक्त जमीनो को आरक्षित किया गया है। रेस्पोंडेन्ट का उक्त आराजीयात से कोई ताल्लुक नहीं है, न ही रेस्पोंड का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त रहा है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध है। अतः मातहत अदालत के उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।
6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोंड ने कथन किया कि विवादित आराजीयात का रेस्पोंडेन्ट सं० 01 रिकार्डेड खातेदार हैं। जिसके पूख्ता साक्ष्य मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली की पत्रावली बउन्नवान छोटू उर्फ छोटेलाल बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी में उपलब्ध है। अपीलांटस् का विवादित आराजीयात से कोई वास्ता नहीं हैं। अपीलांटस् विवादित आराजीयात पर जबरन हक बताकर अतिक्रमण करना चाहते है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.16 पूर्णरूपेण उचित फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

संबन्धित अधिकारियों की सहस्र पर मंचन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों को असलोकन किया गया।

सिवार्ड के असलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2062 चाके माम केसपुरा, मातदार क्षेत्र खुम्डा में आराजीयात खसरा नम्बर 06 लगायत 17 कुल कित्ता 13 रकवा 13 बीघा 06 बिसवा छोटेलाल पुत्र धोलू मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी संवत् 2026-29 से हाल गिरदावरी में खातेदार छोटे पुत्र धोलू मीना के नाम अंकन हैं अतिलत मातहत उपखण्ड अधिकारी कशौली की पत्रावली में अपीलान्त/प्रतिवादीगण के पक्ष को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज शामिल मिसल नहीं है।

अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनसे यह साबित नहीं हो रहा है कि उनमें अंकित खसरा नम्बरान से नए या पुराने कौन-कौन से खसरा नम्बर बने हैं और क्या बाद में वर्णित विवादित आराजीयात के पुराने या नवीन खसरा नम्बर कौन-कौन से हैं? अर्थात् बंदोबस्त विभाग के मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किए गए हैं, जिससे अपील में अंकित तथ्य साबित हो सके।

अपीलान्त के नाम तथा विवादित आराजीयात का अंकन दर्ज रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है? अर्थात् क्या वे रिकार्डें खातेदार हैं? इस तथ्य को भी साबित करने में अपीलान्त असफल रहे हैं। अर्थात् ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर पेश नहीं है।

9. समर्भुक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त साबित करने में असफल रहने से सारहीन माए जाने के कारण खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी कशौली के मुकदमा नम्बर 175/2005 निर्णय व डिक्री 15.12.16 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

10. पत्रावली फौसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 05.01.2023 को सुनाया गया।

(हरि सम मीना) 2023
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर